Power Grid Corporation of India, if so, the action being taken by Government in this regard;

(b) whether the said proposal is likely to entail a reduction in the PGC holding by 26 to 30 per cent;

(c) whether Government are considering this proposal;

(d) whether the proposal is unacceptable to Government; if so, the reasons for which the same is being considered; and

(e) the States which have entered into power purchase agreements with the U.K. firm alongwith their reaction on the raised equity of the U.K. firm to 70%?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) No, Sir. No such proposal has been received by the Government.

(b) to (d) Do not arise in view of the above.

(e) National Grid, UK has not entered into any Power Purchase Agreement with any State/State Electricity Board.

Award of Ratna-R Series Oilfields to Essar Premier Oil Combine

*315. SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the award of Ratna-R series discovered oilfields to the Essar Premier Oil Combine was a pre-determined exercise on the part of the technical evaluation committee and the empowered committee;

(b) whether it is also a fact that the said pre-determined action of the two committees has cost the Government over US $ 500 million;

(c) if so, whether any pay-offs were involved; and

(d) if so, whether the CBI has been ordered to enquire into the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) No, Sir.

मध्य प्रदेश की लंबित जल प्रदाय योजनाएं

*316. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के पास, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई बीस हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों की जल-प्रदाय योजनाएं, स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी योजनाएं कब-कब से लंबित हैं; और

(ग) उपर्युक्त योजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेस्वरलू): (क) और (ख) बीस हजार से कम आबादी वाले शहरों के लिए सुलभ जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत 45 स्कीमें मंजूरी हेतु लंबित हैं। उपर्युक्त में से 43 स्कीमें 1995-96 में 2 स्कीमें 1996-97 में प्राप्त हुईं।

(ग) इस कार्यक्रम हेतु 8वीं योजना में नियत 50.00 करोड़ रुपये की राशि में से मध्य प्रदेश का हिस्सा 7.85 करोड़ रुपये है। स्कीमों की लागत केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में वहन करनी होती है, इस प्रकार मध्य प्रदेश के लिए मंजूर की जाने वाली स्कीमों की कुल लागत 15.70 करोड़ रुपये बैठती है। उपर्युक्त की तुलना में, मध्य प्रदेश में 36.05 करोड़ रुपये की लागत वाली 51 स्कीमें पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं। अतिरिक्त स्कीमें मंजूर करना, पहले जारी धनराशि के उपयोग और 1996-97 के दौरान तथा 9वीं योजना में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।